प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

07.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार से हिमाचल की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राजस्व घाटा अनुदान बहाल करने और विशेष आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया है। शिमला में आज कुल्लू, मण्डी और शिमला जिले के विधायकों के साथ हुई बैठक में उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान बंद करने से प्रदेश को करीब 50 हजार करोड़ रूपए का नुकसान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से राज्य की विकास योजनाएं प्रभावित होंगी और कल्याणकारी योजनाओं सहित वेतन और पैंशन पर भी विपरीत असर पड़ने की संभावना है।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने तीन वर्षों में अपने संसाधनों से 26 हजार 6 सौ 83 करोड़ रूपए का राजस्व अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को वाईल्ड फ्लावर हॉल होटल के स्वामित्व से करीब चार सौ एक करोड़ रूपए का वित्तीय लाभ हुआ है और हर वर्ष 20 करोड़ रूपए की आय होने का अनुमान है।

अग्निहोत्री

उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार एक सशक्त डिजिटल इको सिस्टम के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऊना के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में आज एक समारोह में उन्होंने ड्रोन तकनीक ओर रोबोटिक्स के क्षेत्र में कार्य करने पर विशेष रूप से बल दिया। अग्निहोत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन तकनीक की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस हुई। उन्होंने कहा कि ऐसे अनुभव दर्शाते है कि भविष्य में सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक की भूमिका अत्यंत निर्णायक होगी। अग्निहोत्री ने युवाओं और तकनीकी संस्थानों से इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने का आहवान किया ताकि भारत ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बन सके।

विक्रमादित्य सिंह

केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद किए जाने के फैसले का राज्य में विरोध जारी है। इस मुददे पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल को इस तरह की मदद पहले भी मिलती रही है और आगे भी मिलना जरूरी है।

उन्होंने आज शिमला में कहा कि ये मुददा केवल भाजपा या कांग्रेस की राजनीति का नहीं बल्कि प्रदेश के 75 लाख लोगों के हित का है।

सुरेश कश्यप

भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक करार दिया है। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों का लोगों को सीधा लाभ मिल सके। इस बात का बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि बजट में मुख्य रूप से आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन सहित आम लोगों की उम्मीदों का भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है।

विनय कुमार

सिरमौर जिले में रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में बनने वाली रेणुका बांध परियोजना की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने इस प्रक्रिया को क्षेत्र के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि बांध से प्रभावित परिवारों की सूची में अब एक सौ 50 भूमिहीन और आवासहीन लोगों को भी शामिल किया गया है, जिससे इन परिवारों को भी राहत और न्याय मिल सकेगा। विनय कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सरकार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है और आने वाले समय में कई बड़े फैसले जनता के हित में लिए जाएंगे।